25)

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 👫 अप्रैल, 2017

विषय— मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोर्सिंग के 09 पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0—398/XXXVI(1)/2016-234/2001 दिनांक 21.09.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0—91/XXXVI(1)/2012-234/2001 दिनांक 26.04.2012 द्वारा मां उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोर्सिंग के सृजित कुल 09 पदों की वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत निरन्तरता दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2— उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0—04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014—न्याय प्रशासन—00—भारित—102—उच्च न्यायालय—03—उच्च न्यायालय—00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
- 3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—01 भारित/XXVII(5)/2017-18 दिनांक 10.04.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा) प्रमुख सचिव

संख्या (95 () /XXXVI(1)/2017-234/2001 तदिनांकित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।

2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।

3— वित्त अनुभाग–5 / कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4- एन०आई०सी० / गार्ड फाईल।

(महेश चन्द्र कौशिवा) भपर सचिव

आज्ञा से,